

इज़राइल-फलिस्तीन संघर्ष और दू स्टेट सॉल्यूशन

इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में इज़राइल और फलिस्तीन के बीच 'दू-स्टेट सॉल्यूशन' की संभावनाओं व संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम वृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।

संदर्भ:

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय** (International Criminal Court-ICC) ने **इज़राइल-फलिस्तीन संघर्ष** से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रादेशिक कषेत्राधिकार के दायरे के संदर्भ में एक निरिण्य जारी किया। इसके तहत ICC ने इज़राइल-फलिस्तीन विवाद के दौरान होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच करने पर सहमति विक्रत की है।

फलिस्तीनी अधिकारियों ने ICC के इस फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर, इज़राइल ने ICC की कार्रवाई को एक गैर-कानूनी हस्तक्षेप बताते हुए इसकी आलोचना की है और कहा कि यह कार्रवाई उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करती है। साथ ही इज़राइल ने धमकी दी है कि यह कदम अंततः इज़राइल और फलिस्तीन के बीच दो-राज्य समाधान या 'दू स्टेट सॉल्यूशन' (Two-State Solution) की संभावनाओं को समाप्त कर सकता है।

वर्तमान में इज़राइल-फलिस्तीन तनाव अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले संघर्ष के रूप में बना हुआ है, हालाँकि कई बार कुछ अंतराल के बाद इस कषेत्र की हस्तियां में वृद्धि भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही इस कषेत्र में राजनीतिक विचारों का लगातार क्षण देखने को मिलता है। यह खतरनाक यथास्थितिक्षेत्र की स्थायी शांतिको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है और इस कषेत्र को एक बार पुनः अस्थरिता की ओर धकेल सकती है।

क्या है दू स्टेट सॉल्यूशन?

- दू स्टेट सॉल्यूशन दशकों से चल रहे इज़राइल-फलिस्तीन संघर्ष में शांतिबिहाल करने के प्रयासों का प्राथमिक केंद्र रहा है।
- इस समाधान के तहत इज़राइल के साथ एक स्वतंत्र फलिस्तीनी राज्य (देश) की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत की गई - अरथात् दो अलग समुदायों के लोगों के लिये दो अलग राज्य।
- सैद्धांतिक रूप से यह इज़राइल की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के साथ ही उसे एक यहूदी बाहुल्य आबादी बनाए रखने की अनुमति देता है और फलिस्तीनियों के लिये अलग देश की व्यवस्था का प्रावधान करता है।
- वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना (Partition Plan) इज़राइल और फलिस्तीन के बीच दशकों तक सैन्य कार्रवाई और हस्तियां का कारण बनी। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थिता के बाद मैड्रिड शांतिसमझौते में इज़राइल-फलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिये दू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमति दिनी।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक 'दू स्टेट सॉल्यूशन', जहाँ फलिस्तीन और इज़राइल की वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्वीकार करता है, वहाँ इस कषेत्र में स्थायी शांतिका आधार बन सकता है।

दू स्टेट सॉल्यूशन से जुड़े जोखिम:

- **ईरान का पहलू:** इज़राइल की उत्तरी सीमा पर अभी भी तनाव और जोखिम की स्थितिबनी हुई है, विशेष रूप से ईरानी और हजिबुल्ला के लक्ष्यों (फलिस्तीन से जुड़े) के खिलाफ सीरिया में इज़राइल के हमलों तथा हाल ही में यू.एस. द्वारा ईरानी कमांडर कासमि सुलेमानी की हत्या के बाद यह क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया है।
- **कषेत्रीय शीत युद्ध:** मध्य-पूर्व क्षेत्र वर्तमान में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक क्षेत्रीय शीत युद्ध का सामना कर रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र में कई छोटे परंतु घातक सैन्य समूहों का उदय हुआ है।

- उदाहरण के लिये यमन में सक्रिय हूती लड़ाके, ये समूह अधिक क्षमता हासिल कर इस क्षेत्र में गंभीर अस्थरिता की स्थितिपैदा कर सकते हैं।

- ये सभी कारक अस्थरिता और एकल या एक से अधिक मोरचों पर युद्ध की संभावना को बढ़ाते हैं।
- **तीसरा इंतिफादा:** अंततः ये स्थितियाँ एक तीसरे इंतिफादा का कारण बन सकती हैं और वर्तमान में सक्रिय शांतिपूर्ण प्रतिरोध चरम हस्ता तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन में बदल सकता है।
- **फलिस्तीन में विभाजित राजनीतिक नेतृत्व:** वर्तमान में फलिस्तीनी राजनीतिक नेतृत्व में समन्वय का व्यापक अभाव है, गौरतलब है कि जहाँ

वेस्ट बैंक (West Bank) में फलिस्तीनी राष्ट्रवादियों द्वारा 'टू स्टेट सॉल्यूशन' का समर्थन किया जाता है, वहीं गाजा का राजनीतिक नेतृत्व इज़राइल को मान्यता नहीं देता है।

इंतिफादा (Intifada):

- इंतिफादा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में हुए फलिस्तीनियों के दो प्रसदिध विद्रोह हैं जिनका उद्देश्य उन क्षेत्रों पर इज़राइल के कब्जे को समाप्त करना और एक स्वतंत्र फलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना था।
- पहला इंतिफादा दसिंबर 1987 में शुरू हुआ और सितंबर 1993 में पहले **ओसलो समझौते** पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, इस समझौते ने इज़राइल और फलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता की एक रूपरेखा प्रदान की।
- दूसरा इंतिफादा (जिसे अल-अकसा इंतिफादा भी कहा जाता है) सितंबर 2000 में शुरू हुआ था।
- इन दोनों विद्रोहों में लगभग 5,000 से अधिक फलिस्तीनी और लगभग 1,400 इज़राइली मारे गए।

आगे की राह:

- **भारत की भूमिका:** ऐतिहासिक रूप से भारत ने टू स्टेट सॉल्यूशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये दोनों पक्षों के नेतृत्व से सीधी वार्ताओं में शामिल होने का आग्रह किया है।
 - फलिस्तीन में भारतीय प्रयास फलिस्तीनी अरथव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले भारत-फलिस्तीन विकास साझेदारी के माध्यम से राष्ट्र-नरिमान और संस्थानों को सुदृढ़ करने पर केंद्रति रहे हैं।
 - इज़राइल के साथ भारत रक्षा, विज्ञान और तकनीक आदिके क्षेत्रों में एक विशेष संबंध साझा करता है।
 - इस संदर्भ में भारत इन दोनों देशों को स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा करने हेतु अपनी नरम शक्ति का लाभ उठा सकता है।
- **अब्राहम एकारड़, एक सकारात्मक कदम:** इज़राइल और यूरेंस, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिये हुआ हालयि समझौता, जिसे **अब्राहम एकारड़** (Abraham Accord) के रूप में जाना जाता है, भी इस बात का प्रमाण है कि प्रत्यक्ष वार्ता ही इस क्षेत्र में शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपयुक्त वकिलपूर्ण है।
 - अतः सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम एकारड की तर्ज पर दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापना के लिये प्रयास करना चाहयि।

नाष्करण:

वर्तमान में इज़राइल-फलिस्तीन विवाद के शांतपूर्ण समाधान के लिये विश्व के सभी देशों को एक साथ आने की आवश्यकता है, परंतु इज़राइल सरकार तथा इस मामले से जुड़े अन्य हितधारकों की अनियंत्रित विवादों को और अधिक बढ़ावा देना चाहयि। ऐसे में इज़राइल-फलिस्तीन मुद्दे के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण भारत के लिये अरब देशों और इज़राइल के साथ अनुकूल संबंध बनाए रखने में सहायक होगा।



अभ्यास प्रश्न: इज़राइल और फ़लिस्तीन के बीच 'दू-स्टेट सॉल्यूशन' की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए इसके प्रभाव की समीक्षा कीजिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/elusive-two-state-solution>